

ये जीवन है,  
उलझेंगे नहीं  
तो सुलझेंगे कैसे।  
- अज्ञात



## राजनीतिक स्तर पर पहल जरूरी

चीन और अमेरिका के बीच डेढ़ साल से जारी ट्रेड वॉर ने पिछले साल हांगकांग में विद्रोही गतिविधियां शुरू होने के साथ अलग ऊंचाई पकड़ी और इधर कोरोना वायरस का सिलसिला चल पड़ने के बाद तो इसने लगभग शीतयुद्ध जैसी शक्ति अख्तियार कर ली है।

रवि कुमार।

भारत और चीन के बीच लड़ाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओएसी) पर पिछले कुछ दिनों से देखे जा रहे तनाव ने काफी गंभीर रूप ले लिया है। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के लड़ाख दौरे के बावजूद गतिरोध समाप्त होने के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मामला तीन साल पहले तिब्बत-सिक्किम-भूटान त्रिकोण पर पैदा हुई डोकलाम जैसी स्थिति के दोहराव की ओर न जाए, इसके लिए अब राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर पहल जरूरी है।

एक बात स्पष्ट है कि दोनों देश अपनी जमीन को लेकर सजग हैं और दोनों में से एक का हिस्सा दूसरा एक इंच भी दबा ले, यह अब दूर की कौड़ी हो चुकी है। अच्छा होता कि सत्तर साल से भी ज्यादा

समय से स्वतंत्र व्यवस्था का संचालन कर रही भारत और चीन की सत्ताएं आपसी सीमा को स्थायी रूप देतीं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें सीमा विवाद को फ्रिज में रखकर अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते बढ़ाने पर काम जारी रखना चाहिए।

दरअसल, एलओएसी की कुछ छिटपुट हरकतों के अलावा कुछ बाहरी मामलों ने भी हाल के तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया है। चीन और अमेरिका के बीच डेढ़ साल से जारी ट्रेड वॉर ने पिछले साल हांगकांग में विद्रोही गतिविधियां शुरू होने के साथ अलग ऊंचाई पकड़ी और इधर कोरोना वायरस का सिलसिला चल पड़ने के बाद तो इसने लगभग शीतयुद्ध जैसी शक्ति अख्तियार कर ली है।

भारत के रिश्ते पिछले कई वर्षों से

अलग-अलग अमेरिका और चीन, दोनों के साथ काफी अच्छे रहे हैं और दोनों से हमारा व्यापार लगातार बढ़ता गया है। लेकिन दुनिया की इन नंबर एक और दो ताकतों के बीच जबर्दस्त कटुता ने बाकी दुनिया में जो कन्फ्यूजन पैदा किया है, उसका शिकार एक हद तक भारत भी हुआ है। हमारे राजनीतिक दायरे में एक ताकतवर बड़ा हिस्सा अभी के वैश्विक ध्रुवीकरण में चीन के खिलाफ खड़ा होकर अमेरिका के करीब दिखना बेहतर मानता है।

ताइवानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सत्तारूढ़ दल के दो सांसदों की वर्चुअल मौजूदगी चीन के राजनयिक दायरे में एक परीक्षा शत्रुतापूर्ण संकेत के रूप में देखी जा रही है। ऐसी चीजें अनुच्छेद 370 के खात्मे की संसदीय

पहल से जुड़कर मौजूदा सीमा विवाद को डोकलाम प्रकरण से आगे ले जा सकती हैं। अगर जरूरी हो जाए तो इस रास्ते पर आगे बढ़ने में भी हमें कोई हिचक नहीं होगी, लेकिन असल बात वही है कि हम जो भी करें, अपनी राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर करें, किसी और को हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की इजाजत हरगिज न दें। भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा दुनिया की सबसे लंबी खुली सीमा है और आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से एक-दूसरे के खिलाफ एक भी गोली न चलने का समझदार इतिहास इससे जुड़ा है। यह सिलसिला आगे चलता रहे, इसे सुनिश्चित करके ही दोनों देशों का राजनीतिक नेतृत्व इस सदी को एशिया की सदी बनाने की राह पर आगे बढ़ सकता है।

## जीवन के इंचार्ज

**अशोक बोहरा।**  
आपको यह बात समझनी चाहिए कि आप स्वयं अपने जीवन के इंचार्ज हैं... अगर आपको लगता है कोई और आकर आपकी मदद करेगा या आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालेगा तो आपका यह इंतजार बहुत लंबा चलता जाएगा। ध्यान वो तरीका है जिसके जरिए हम अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की उन्नति के लिए समय समर्पित करते हैं। ध्यान ना सिर्फ आपके आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है बल्कि यह आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत का भी ध्यान रखता है... इस ओर से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। शांति के अहसास और स्वास्थ्य ने मेरे अंदर से परोपकारिता के विचार चुरा लिए हैं। मैं असंतोष के सारे भाव भूल जाती हूँ और अपने पुराने अस्तित्व को याद करती हूँ। मैं इस आंतरिक शांति को याद करती हूँ।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### साहित्य और कला

फेसबुक पर लाइव कार्यक्रमों का सिलसिला तेज हो गया है। कविताएं पढ़ी जा रही हैं, विचार-विमर्श हो रहे हैं। सेमिनार की जगह वेबिनार हो रहे हैं, यानी वेब पर होने वाला सेमिनार। वह सब कुछ, जो पत्र-पत्रिकाओं में हुआ करता था, अब सोशल मीडिया पर हो रहा है। गौर करने की बात है कि जो तबका अभी इस माध्यम में काफी सक्रिय है, वह हाल तक इसको संदेह की दृष्टि से देखता था। इसे अंगभीर लोगों का मंच कहा जाता था। यहां तक कहा गया था कि फेसलेस लोग ही फेसबुक पर रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में साहित्यिक गतिविधियों का एकमात्र मंच अब सोशल मीडिया ही हो गया है। दरअसल किसी भी नई तकनीक का शुरु में विरोध होता ही है। 1985-86 में जब देश का कंप्यूटरीकरण हो रहा था तो श्रमिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों ने भी कंप्यूटर का विरोध किया था। लेकिन आज कंप्यूटर के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए, आज अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता। आज यह कितना बड़ा सहारा दिख रहा है। तकनीक जीवन को कितना बदल देती है। आज से कुछ साल पहले तक कौन सोच सकता था कि आप अपने घर में बैठकर मोबाइल के सामने कविता पढ़ेंगे और अपने-अपने घरों में बैठे बहुत सारे लोग उसे देख रहे होंगे। कौन सोच सकता था कि अपने घरों में बैठकर एक ही विषय पर अलग-अलग वक्ता अपने विचार व्यक्त कर रहे होंगे और लोग भी अपने घरों से ही सुन रहे होंगे। अगर कोरोना महामारी का यही स्वरूप लंबे समय तक बना रह गया तो कितनी चीजें बदल जाएंगी। हो सकता है लोग छपे हुए अखबार और पत्रिकाएं पढ़ना भूल जाएं। फिर किताबें छापने का भी क्या मतलब रहेगा?

नीति-निर्धारकों का मानना रहा कि उद्योगपति मजबूत होंगे तो देश खुद-ब-खुद मजबूत हो जाएगा। आज आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हम कहां हैं?

## महाशक्ति नहीं बन पाएंगे

शिवेंद्र कुमार

भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की आप दिन चर्चा होती है। 5 ट्रिलियन डॉलर की बात आजकल खूब हो रही है। आखिर यह सब कैसे होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके जवाब तलाशने की जरूरत है। आजादी के बाद हमारे यहां जितनी नीतियां बनीं सभी के केंद्र में उद्योगपति रहे। मजदूर उनके केंद्र में कभी नहीं आए। नीति-निर्धारकों का मानना रहा कि उद्योगपति मजबूत होंगे तो देश खुद-ब-खुद मजबूत हो जाएगा। आज आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हम कहां हैं? क्या हमने जो सपना देखा था उसे पूरा कर लिया? अगर हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो कमियां कहां रहीं, इसे समझने की जरूरत है। सैद्धांतिक रूप से यह सभी सरकारों ने माना कि देश की जो कमजोर कड़ियां हैं, जब तक वे मजबूत नहीं होंगी देश मजबूत नहीं होगा। लेकिन, इनकी मजबूती के लिए किसी सरकार द्वारा खास व्यावहारिक प्रयास नहीं किए। इस देश की सबसे कमजोर कड़ी है 'असंगठित क्षेत्र'। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। देश के कुल वर्किंग फोर्स में इनका हिस्सा 95 फीसदी से भी ज्यादा का है। इसमें प्रवासी मजदूर, छोटे कारीगर, सीमांत किसान, स्वरोजगार के माध्यम से



छोटे-छोटे व्यापार कर रहे लोग शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या करीब 45 से 50 करोड़ के बीच है। जब तक यह समाज मजबूत नहीं होगा हम आर्थिक क्या, किसी तरह के महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। विडंबना देखिए, यह समाज (असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग) आर्थिक रूप से भले कमजोर हैं, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद संपन्न हैं। लेकिन, दूसरी तरफ देश का दुर्भाग्य देखिए बड़ी संख्या होने के बावजूद हमने नीतियों के केंद्र में इन्हें कभी नहीं रखा। इनको मजबूत किए बिना हम कभी महाशक्ति नहीं बन सकते हैं। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों से हम महाशक्ति तो कतई नहीं बन सकते हैं। हम

इसे जितनी जल्दी समझ लें हमारे लिए बेहतर होगा। वास्तव में यह असंगठित वर्ग देश की रीढ़ है। सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी। इन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना महामारी ने इनका बड़ा नुकसान किया है। ये जहां थे वहां से काफी पीछे चले गए हैं। हालांकि, सरकारों के साथ-साथ कुछ जागरूक समाज के लोगों ने इनकी मदद की, लेकिन वह नाकाफी है। इस महामारी में इन लोगों ने काफी कुछ खोया है।

सरकार को इनके जीवनशैली को ध्यान में रखकर मदद करने की जरूरत है। सरकार को आगे की नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि आजादी के बाद हम जिस रास्ते पर आगे बढ़े हैं, वह कितना स्थाई है। सिर्फ दो महीने के एक संकट से यह मॉडल पूरी तरह से धराशायी होता दिख रहा है। अब नीति-निर्धारकों के साथ-साथ पूरे समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें अपनी योजना बनाते समय इस कमजोर कड़ी को यानी असंगठित क्षेत्र के लोगों को केंद्र में रखना होगा। बिना इनके मजबूती के हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। अभी ये खास संकट में हैं। मूल रूप से ये स्वावलंबी स्वभाव के हैं। इनकी जरूरतें सीमित हैं। इस संकट की घड़ी में सरकार को इनकी दैनिक जरूरत की चीजों को ध्यान में रखकर इनका सहयोग करना चाहिए।

सूट्टीकू नवताल-5366									
		2						3	
		9		8				2 6 4	
1				3 6				9	
4		3							1
		8		2				8	6
		4		7 5					3
		3 7 5		4				1	
		2						8	

## अपना ब्लॉग सामूहिक प्रयास जरूरी

**मोहन।** कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है, यह घोषणा भी वित्त मंत्री ने की। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग को अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की और मोहलत दी गई है। अफ्लिकेबिलिटी ऑफ दि कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट-2020 जो पहले वित्त वर्ष 2019-20 में आने वाली थी, अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टाल दी गई है। किसी कंपनी के डायरेक्टर के लिए देश में कम से कम 182 दिन रहना जरूरी था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसी अनेक घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा की गईं जिससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी। उसके बाद उन्होंने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा।

